













# सालाना 8 प्रतिशत GDP रही तो 2047 तक 55 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेगा भारत: केवी सुब्रमण्यन

परिवहन विशेष न्यूज

अगर भारत 8 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर बनाए रखता है तो 2047 तक भारत 55 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है। सुब्रमण्यन ने कहा कि मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि अगर भारत अब से लेकर 2047 तक 8 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ सकता है जब हम स्वतंत्रता के 100वें वर्ष का जश्न मनाएंगे तो यह 55 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है।

**नई दिल्ली।** अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के कार्यकारी निदेशक और भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार K.V. Subramanian ने गुरुवार को कहा कि अगर भारत 8 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर बनाए रखता है, तो 2047 तक भारत 55 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है।

### 2047 तक बनेगी 55 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था

समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए सुब्रमण्यन ने कहा कि मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि अगर भारत अब से लेकर 2047 तक 8 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ सकता है, जब हम स्वतंत्रता के 100वें वर्ष का जश्न मनाएंगे, तो यह 55 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है। उन्होंने स्वीकार किया कि यह लक्ष्य अन्य पूर्वानुमानों की तुलना में महत्वाकांक्षी लगता है, जैसे कि अन्स्ट्रॉड यंग का 2047 के लिए 26



ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का पूर्वानुमान या गोल्डमैन सैक्स का 2075 तक 50 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुमान है। उन्होंने कहा कि अगर हम 2016 के बाद सरकार द्वारा मुद्रास्फीति-लक्ष्यीकरण सहित सभी व्यापक आर्थिक विविधताओं को ध्यान में रखते हैं, जिसके परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति में औसतन कम से कम 2 प्रतिशत की कमी आई है। यह डॉलर के मुकाबले रुपये के मूल्य में उल्लेखनीय रूप से कम गिरावट को दर्शाता है और जब इसे चक्रवृद्धि की शक्ति

में जोड़ा जाता है, तो 26 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का पूर्वानुमान कमतर आंका जाता है। **ऐसे छुपे आंकड़े** 55 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य पर सुब्रमण्यन ने समझाया कि अगर हम 5 प्रतिशत मुद्रास्फीति के साथ वास्तविक रूप से 8 प्रतिशत की वृद्धि मान लें, जो मुद्रास्फीति लक्ष्य व्यवस्था के बाद 2016 से मामला रहा है। यह 13 प्रतिशत है, अगर मुद्रास्फीति की काफी कम दर के कारण मुद्रा का मूल्यहास 1 प्रतिशत है, तो मुद्रा का मूल्यहास लगभग 3 के

एतिहासिक औसत की तुलना में बहुत कम होगा। तब विकास दर 12 प्रतिशत होगी। **अमेरिका और चीन को देंगे टक्कर** उन्होंने यह भी कहा कि 2047 में भारत से आगे दो अर्थव्यवस्थाएं अमेरिका और चीन होंगी। भारत की प्रति व्यक्ति आय 40,000 अमेरिकी डॉलर होगी। सुब्रमण्यन ने इस बात पर जोर दिया कि 8 प्रतिशत की विकास दर और नियंत्रित मुद्रास्फीति के साथ भारत 2047 तक 55 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल कर सकता है।

## RBI के पास वापस आए 2,000 रुपये के 97.92 प्रतिशत नोट; 7,409 करोड़ रुपये के नोट अब भी आने बाकी

RBI ने बृहस्पतिवार को कहा कि 2000 रुपये के 97.92 प्रतिशत नोट बैंकों में वापस आ गये हैं। आरबीआई ने 19 मई 2023 को 2000 रुपये मूल्य के बैंक नोट को चलन से हटाने की घोषणा की थी। 19 मई 2023 की स्थिति के अनुसार उस समय चलन में 2000 रुपये के बैंक नोट का कुल मूल्य 3.56 लाख करोड़ रुपये था।

**नई दिल्ली।** भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बृहस्पतिवार को कहा कि 2,000 रुपये के 97.92 प्रतिशत नोट बैंकों में वापस आ गये हैं। चलन से हटाये गये केवल 7,409 करोड़ रुपये मूल्य के नोट अब लोगों के पास हैं। आपको बता दें कि नवंबर, 2016 में 1,000 रुपये और 500 रुपये के बैंक नोट को चलन से हटाने के बाद 2,000 रुपये के बैंक नोट जारी किये गये थे।

**97.92 प्रतिशत नोट वापस आए** आरबीआई ने 19 मई, 2023 को 2,000 रुपये मूल्य के बैंक नोट को चलन से हटाने की घोषणा की थी। 19 मई, 2023 की स्थिति के अनुसार उस समय चलन में 2,000 रुपये के बैंक नोट का कुल मूल्य 3.56 लाख करोड़ रुपये था। ये आंकड़ा 31 जुलाई, 2024 को घटकर 7,409 करोड़ रुपये रह गया है। केंद्रीय बैंक ने बयान में कहा कि इस प्रकार 19 मई, 2023 तक चलन में मौजूद 2,000 रुपये



के 97.92 प्रतिशत बैंक नोट वापस आ गये हैं। **अभी भी हो सकते हैं जमा** दो हजार रुपये के बैंक नोट को जमा करने या बदलने की सुविधा सात अक्टूबर, 2023 तक देश की सभी बैंक शाखाओं में उपलब्ध थी। चलन से हटाये गये 2,000 रुपये के बैंक नोट को बदलने की सुविधा 19 मई, 2023 से रिजर्व बैंक के 19 निर्गम कार्यालयों में उपलब्ध है। आरबीआई के निर्गम कार्यालय 9 अक्टूबर, 2023 से बैंक खातों में जमा करने के लिए भी 2,000 रुपये के बैंक नोट स्वीकार कर रहे हैं। इसके अलावा लोग देश के भीतर भारतीय डाक से भी 2,000 रुपये के नोट आरबीआई के किसी भी निर्गम कार्यालय में भेज रहे हैं। यह पैसा उनके बैंक खाते में जमा हो जाता है। **19 आरबीआई कार्यालय हैं एक्टिव बैंक नोटों को जमा/विनिमय करने वाले** 19 आरबीआई कार्यालय अहमदाबाद, बैंगलुरु, बिलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नयी दिल्ली, पटना और तिरुवनंतपुरम में हैं।

## HDFC Bank ने ग्राहकों को किया सतर्क, फेक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से सावधान रहने की दी सलाह



HDFC Bank देश का सबसे बड़ा बैंक है। बैंक ने ग्राहकों को ऑनलाइन फ्रॉड को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है। बैंक के बयान के अनुसार ऑनलाइन फ्रॉड के मामलों में तेजी देखने को मिली है। ग्राहक फेक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के झांसे में आ जाते हैं। इन प्लेटफॉर्म पर हाई रिटर्न का वादा किया जाता है जो ग्राहकों को आकर्षित करता है। ऐसे में ग्राहकों को सतर्क होना चाहिए।

**नई दिल्ली।** देश के सबसे बड़े बैंक यानी एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) ने ग्राहकों को फेक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को लेकर सतर्क किया है। बैंक ने कहा कि इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के मामलों में वृद्धि देखने को मिली। लगातार बढ़ रहे फ्रॉड को रोकने के लिए

ग्राहकों का सतर्क होना बहुत जरूरी है। बैंक ने ग्राहकों को निवेश के अवसर देने वाली फेक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से सावधान रहने की सलाह दी है। एचडीएफसी बैंक के बयान के अनुसार कई बार निवेशक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आने वाले ज्यादातर आकर्षक ऑफर की जाल में फंस जाते हैं और बाद में फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए ग्राहकों का जागरूक होना बेहद जरूरी है। **हाई रिटर्न का वादा** आमतौर पर स्टॉक, आईपीओ, क्रिप्टोकॉर्सी, बिटकॉइन आदि में निवेश को लेकर फ्रॉड के मामले देखे गए हैं। इनमें ग्राहकों को हाई रिटर्न का वादा करने का झांसा दिया जाता है। जालसाज फेक

इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म या ऐप का निर्माण करते हैं जो कि ग्राहकों को ऑरिजनल जैसा लगता है। इन ऐप्स या वेबसाइट पर उच्च रिटर्न का संकेत देने वाले फर्जी डैशबोर्ड शो होता है। इस फर्जी डैशबोर्ड पर शो हो रहे रिटर्न को देखकर ग्राहक जालसाज का शिकार हो जाते हैं। "हम निवेश धोखाधड़ी के मामलों की संख्या में वृद्धि देख रहे हैं और इस मुद्दे के बारे में व्यापक जागरूकता और ज्ञान पैदा करने में मदद करना चाहते हैं, ताकि उपभोक्ता इन भ्रामक योजनाओं का शिकार होने से बच सकें। जबकि सरकार, बैंक और नियामक निकाय इन धोखाधड़ी को रोकने के लिए कदम उठा रहे हैं। व्यक्तिगत सतर्कता और जागरूकता इन फ्रॉड से बचने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।"

परिवहन विशेष न्यूज

सरकार शुक्रवार से दिल्ली-एनसीआर और मुंबई के रिटेल मार्केट में 50 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर टमाटर बेचना शुरू करेगी। 29 जुलाई को केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने दिल्ली-एनसीआर में 60 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर टमाटर की बिक्री शुरू की थी। टमाटर खरीद सीधे मंडियों से की जाएगी जिससे बिचौलियों से बचा जा सके। **नई दिल्ली।** आम आदमी को राहत देने के लिए सरकार शुक्रवार से दिल्ली-एनसीआर और मुंबई के रिटेल मार्केट में 50 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर टमाटर बेचना शुरू करेगी। बाजार में अभी टमाटर 60 रुपये प्रति किलोग्राम पर बिक रहा है।

### फिलहाल 60 रुपये प्रति किलोग्राम हो रही बिक्री

29 जुलाई को केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने दिल्ली-एनसीआर में 60 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर टमाटर की बिक्री शुरू की थी। बाद में मुंबई में भी इसकी बिक्री शुरू हो गई।

जोशी ने कहा कि हमारे हस्तक्षेप के बाद टमाटर की कीमतों में कमी आई है। उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने संवाददाताओं से कहा कि हम कल (2 अगस्त) से दिल्ली-एनसीआर और मुंबई में 50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से टमाटर बेचना शुरू करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (NCCF) मोबाइल वैन के जरिए टमाटर बेच रहा है। उपभोक्ता मामलों के विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 31 जुलाई को टमाटर की अखिल भारतीय औसत कीमत 61.74 रुपये प्रति किलोग्राम थी। दिल्ली में बुधवार को औसत कीमत 70 रुपये प्रति किलोग्राम थी। पिछले महीने, कई उत्पादक राज्यों में अनियमित बारिश के बाद गर्म लहरों के कारण आपूर्ति प्रभावित होने से दरें 100 रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक हो गईं। **सीधे मंडियों से हुई खरीद** खरे ने कहा कि मंत्रालय दिल्ली-एनसीआर



के बाजार में अपने सफल स्टोरों के माध्यम से टमाटर बेचने के लिए मदर डेयरी को शामिल करने पर विचार करेगा। इस मामले में मंत्रालय ने मूल्य स्थिरीकरण कोष (PSF) का उपयोग नहीं किया है, क्योंकि टमाटर सीधे मंडियों से खरीदे गए थे। महासंघ थोक मंडियों से टमाटर खरीद रहा है और उन्हें उचित खुदरा कीमतों पर बेच रहा है।

इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खुदरा स्तर पर लाभ मार्जिन उचित रहे और बिचौलियों को अप्रत्याशित लाभ से रोका जा सके और इस तरह उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हो सके। इस हस्तक्षेप से एनसीसीएफ मूल्य वृद्धि को शांत करना और बाजार में मूल्य स्थिरता बनाए रखना चाहता है, जिससे उपभोक्ताओं को लाभ हो सके।

## PNB के कन्ज्यूमर लोन होंगे महंगे, MCLR में 5 बेस प्वाइंट की बढ़ोतरी



**परिवहन विशेष न्यूज** PNB ने एक नियामक फाइलिंग में कहा कि बैंचमार्क एक साल की अवधि का एमसीएलआर जिसका उपयोग ऑटो और पर्सनल जैसे अधिकांश कन्ज्यूमर लोन की कीमत तय करने के लिए किया जाता है। बुधवार को सार्वजनिक क्षेत्र के एक अन्य ऋणदाता बैंक ऑफ इंडिया ने भी एक वर्ष की अवधि के लिए MCLR में 5 आधार अंकों की वृद्धि करके इसे 8.95 प्रतिशत करने की घोषणा की है। **नई दिल्ली।** सरकारी स्वामित्व वाले Punjab National Bank ने गुरुवार को सभी अवधियों के लिए सीमांत लागत आधारित ऋण दर (MCLR) में 0.05 प्रतिशत या 5 बेस प्वाइंट की बढ़ोतरी की है। PNB के इस फैसले के बाद अधिकांश कन्ज्यूमर लोन महंगे हो गए हैं। **महंगा हो गया कन्ज्यूमर लोन** पीएनबी ने एक नियामक फाइलिंग में कहा कि

बैंचमार्क एक साल की अवधि का एमसीएलआर, जिसका उपयोग ऑटो और पर्सनल जैसे अधिकांश कन्ज्यूमर लोन की कीमत तय करने के लिए किया जाता है, पहले की दर 8.85 प्रतिशत के मुकाबले 8.90 प्रतिशत होगा।

**फिलती बढ़ोतरी हुई?** तीन साल का एमसीएलआर 5 बेस प्वाइंट की वृद्धि के साथ 9.20 प्रतिशत है। एक महीने, तीन महीने और छह महीने की अवधि की दर 8.35-8.55 प्रतिशत के दायरे में होगी। ओवरनाइट अवधि पर एमसीएलआर 8.25 प्रतिशत के मुकाबले 8.30 प्रतिशत होगा। नई दरें 1 अगस्त 2024 से प्रभावी होंगी।

**Bank Of India ने भी की बढ़ोतरी** बुधवार को सार्वजनिक क्षेत्र के एक अन्य ऋणदाता बैंक ऑफ इंडिया ने भी एक वर्ष की अवधि के लिए MCLR में 5 आधार अंकों की वृद्धि करके इसे 8.95 प्रतिशत करने की घोषणा की। हालांकि, शेष अवधि के लिए दरें अपरिवर्तित रहें।

